

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 117 / 117 / 2007 ~~2014~~ विरुद्ध आदेश दिनांक 04-10-2006

पारित द्वारा आयुक्त, सागर संभाग, सागर -- प्र0क0 287 अ 19 / 05-06

भरत पुत्र भगवत लोधी

ग्राम डूडा तहसील टीकमगढ़

जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश

विरुद्ध

म0प्र0शासन द्वारा

-- आवेदक

अनावेदक

आवेदक के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा

अनावेदक की ओर से पैनल अभिभाषक

आदेश

(आज दिनांक 12 6 - 2014 को पारित)

आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 287 / अ-10 / 2005 06 अपील में पारित आदेश दिनांक 04-10-2006 के विरुद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत की गई थी, किन्तु आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को निगरानी में बदलकर श्रवण करने का निवेदन स्वीकार कर यह आदेश पारित किया जा रहा है।

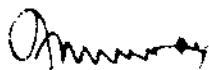
2 / प्रकरण का सारोँश यह है कि आवेदक ने नायब तहसीलदार वृत्त बड़ागोंव (धरान) तहसील टीकमगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम डूडा स्थित भूमि सर्वे नंबर 2431 एवं 2432 क्रमशः रकबा 0.644 हैक्टर एवं 0.450 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर पिछले 30 वर्ष से कब्जा करके खेती करता आ रहा हूँ इसलिये नियमानुसार भूमिस्वामी पदवा प्रदान किया जावे। नायब तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 5 अ 19 / 02 03

पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 2-7-2003 पारित किया एवं वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन आवेदक को कर दिया।

अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ ने भूमि व्यवस्थापन में अनियमितता करना बताते हुये कलेक्टर टीकमगढ़ को प्रतिवेदन दिनांक 1.5.2004 प्रस्तुत किया, जिस पर से कलेक्टर टीकमगढ़ ने आवेदक के विरुद्ध स्वमेव निगरानी क्रमांक 35/2003-04 पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया, आवेदक अभिभाषक सहित उपस्थित हुआ और सूचना उपरांत वाद में जानबूझकर अनुपस्थित हो गया। कलेक्टर टीकमगढ़ ने अनावेदक के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये आदेश दिनांक 9-8-04 पारित किया तथा भूमि व्यवस्थापन में अनियमिततायें पाने से नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 2-7-2003 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध आवेदक ने आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की, जो प्रकरण क्रमांक 287/अ-10/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 04-10-2006 से निरस्त हुई, इसी आदेश से व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की गई, जिसे निगरानी में परिवर्तित किया गया है।

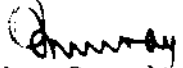
3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि नायब तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 5 अ 19/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 2-7-2003 से वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन आवेदक के हित में किया है। विचार योग्य है कि क्या दिनांक 2 7 2003 को भूमि बंटन/व्यवस्थापन की शक्तियाँ नायब तहसीलदार को थीं? मान. उच्च न्यायालय (डी.बी.) के समक्ष रिट पिटीशन क्रमांक 2496/02 प्रस्तुत हुई है जिसमें पारित आदेश दिनांक 5 8-2002 से बंटन/व्यवस्थापन पर रोक लगा दी गई। इस रोक के क्रम में म0प्र0शासन,राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा ज्ञापन क्रमांक एफ-16-18/2007/सा-2-ए दिनांक 30.6.2007 जारी



किया तथा नायब तहसीलदार/तहसीलदार से बन्टन/व्यवस्थापन की शक्तियाँ वापिस लेकर कलेक्टर में वेष्टित कर दी गई। स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 5-8-2002 से बन्टन/व्यवस्थापन पर रोक के बाबजूद नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 2-7-2003 से वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन आवेदक के हित में करने का अधिकारितारहित आदेश पारित किया है जिसे कलेक्टर टीकमगढ़ ने निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है और इन्हीं कारणों से कलेक्टर के आदेश को आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 287/अ-10/ 2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 04-10-2006 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी अरबीकार की जाती है।


(अशोक शिवहरे)
सदरय
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर